


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 602]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2015/आश्विन 8, 1937

No. 602]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2015/ASVINA 8, 1937

शहरी विकास मंत्रालय

(पी एस पी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 746(अ).—सरकार ने निर्णय लिया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 8 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, भारत के राजपत्र को दिनांक 1 अक्टूबर, 2015 से केवल ई-पब्लिशिंग में बदल दिया जाएगा।

भारत के राजपत्र को सरकारी वेबसाइट www.egazette.nic.in पर अपलोड करके केवल ई-पब्लिश किया जाएगा।

शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रकाशन विभाग उपरोक्त प्रकाशित अधिसूचनाओं का रिकार्ड रखता रहेगा और अपेक्षित होने पर संदर्भ के लिए इसे उपलब्ध कराएगा।

सरकार द्वारा राजपत्र के वास्तविक मुद्रण और हार्ड प्रतियों की बिक्री 1 अक्टूबर, 2015 से पूरी तरह से बन्द कर दी जाएगी। उपयोगकर्ता उपर्युक्त सरकारी वेबसाइट से ऐसे प्रकाशित ई-गजट को निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। इसे विधि कार्य विभाग की सहमति से उनके दिनांक 18 सितम्बर, 2015 के संदर्भ सं. 229536 के तहत जारी किया जाता है।

[फा. सं. ओ-17022/1/2015-पीएसपी-I]

कैलाश चौधरी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(PSP DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2015

G.S.R. 746(E).—The Government have decided that having regard to provisions of Section 8 of the Information Technology Act, 2000, the Gazette of India shall switch to exclusive **e-publishing** with effect from 1st October, 2015.

The Gazette of India shall be only e-published by uploading on the official website www.egazette.nic.in

The Department of Publication under Ministry of Urban Development shall continue to maintain the record of notifications published as above and make available the same for reference whenever required.

The physical printing and sale of hard copies of Gazette by the Government shall cease completely from 1st October, 2015. The users may download the e-gazette so published from above mentioned Official website free of charge. This issues with the concurrence of Department of Legal Affairs vide their reference No. 229536 dated 18th September, 2015.

[F. No. O-17022/1/2015-PSP-I]

KAILASH CHOUDHARY, Under Secy.